Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN(o): 2581-6241
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 7.384
Volume - 7, Issue - 12, December - 2024

DOIs:10.2018/SS/202412012 --:-- Research Paper / Article / Review

इंटरनेट युग में सामुदायिक रेडियो प्रसारण की प्रासंगिकता

डॉ. अनामिका शर्मा
पत्रकारिता एवं जनसंचार
Email - Anamikaa.4sharma@gmail.com

शोध सार: *रेडियो एक लोकप्रिय और महत्वपूर्ण संचार साधन है। मानव सभ्यता के इतिहास में इसका महत्व 'आग या चाक' से कम नहीं आंका जा सकता है। मानव सभ्यता का विकास विभिन्न आविष्कारों के साथ अपनी दिशा तय करता रहा है। इन आविष्कारों ने मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने के साथ साथ मानव समाज में स्थिरता भी लाई है। रेडियो इन्हीं आविष्कारों में से एक है। रेडियो प्रसारण की शुरूआत चरणबद्ध तरीके से हुई वैज्ञानिक अनुप्रयोगों व विचारों का परिणाम है। माना जाता रहा है कि मानव अपने विकास के शुरूआती दौर में विभिन्न आवाजों, चिन्हों और धुएं आदि से संचार करता था। तरंगों के माध्यम से संचार करना निश्चित ही एक क्रांतिकारी विचार था, इस आविष्कार ने जनसंचार के क्षेत्र में एक क्रांति की शुरूआत की । सामुदायिक रेडियो की अवधारणा का जन्म 1940 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में अमेरिका से हुआ । सामुदायिक रेडियो की शुरूआत मुख्यधारा के संचार माध्यमों के विकल्प के रूप में हुई थी । यह समाज के दबे, कुचले, शोषित व उत्पीड़ित वर्ग की आवाज के रूप में उभरा, लेकिन इसका दायरा बढ़ता गया और कालांतर में दुनिया भर में ये विभिन्न प्रकार के रूपों में उपलब्ध होने के साथ साथ विकास संचार और सहभागी संचार के प्रमुख उपकरण के तौर पर मान्यता प्राप्त कर रहा है। भारत में भी विकास के प्रयासों को जन-जन तक पहुंचाने के लिये सामुदायिक रेडियो को महत्वपूर्ण संचार माध्यम माना गया है और इससे जुड़ी विस्तृत पॉलिसी भी बनाई गई है। हालांकि इंटरनेट युग में, द्रुतगामी संचार साधन के रूप में मोबाईल फोन का बढ़ता प्रचलन, सामुदायिक रेडियो की लोकप्रियता को भी प्रभावित कर रहा है। प्रस्तुत अध्ययन भारत में इंटरनेट क्रांति के दौर में सामुदायिक रेडियो प्रसारण की प्रासंगितकता पर प्रकाश डालता है।*

बीज शब्द: *सामुदायिक रेडियो, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इंटरनेट रेडियो, विकास संचार।*

1. प्रस्तावना :

रेडियो प्रसारण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों से संचार के विचार से ही सफल हो पाया। 1865 में ब्रिटिश गणितज्ञ, जेम्स मैक्सवेल ने सबसे पहले तरंगों से संचार के संदर्भ में एक सिद्धांत विश्व पटल पर रखा। हालांकि वे इसे प्रायोगिक तौर पर सिद्ध नहीं कर पाए। आगे चलकर इसी सिद्धांत पर एक जर्मन वैज्ञानिक हेनरी हर्ट्ज ने अपने प्रयोगों से ये सिद्ध किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगो को वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान और एक यंत्र से दूसरे यंत्र तक संचरित किया जा सकता है। इस प्रयोग ने इटली के भौतिक शास्त्री गुलिलमो मारकोनी को प्रेरित किया और उसने 1896 में रेडियो का आविष्कार कर दुनिया को एक अचंभे में डाल दिया **(श्रीधर और मुराडा, 2019)**। रेडियो पर पहला सफल प्रसारण अमेरिका के सेंट पीट्सबर्ग में वर्ष 1920 को किया गया। इसके बाद उस समय के तमाम बड़े देशों ने रेडियो प्रसारण के लिये प्रयास शुरू कर दिये। भारत में भी रेडियो प्रसारण की शुरूआत इसी दौर में मानी जाती है। वैसे तो

भारत में पहला रेडियो प्रसारण 1921 में मुंबई (तात्कालिक बंबई) से पूणे (तात्कालिक पूना) के बीच हुआ, लेकिन रेडियो प्रसारण की विधिवत शुरूआत भारत में 23 जुलाई 1927 को बंबई से हुई **(लूथरा,1986)**। बाद में कलकत्ता, मद्रास में भी रेडियो प्रसारण की शुरूआत हुई। प्रारंभ में प्रसारण रेडियो क्लबों या स्थानीय रियासतों की देखरेख में किया जाता था। लेकिन आर्थिक कारणों से ये रेडियो क्लब ज्यादा समय तक प्रसारण करने में सक्षम नहीं रह पाये। वर्ष 1930 में रेडियो प्रसारण तात्कालिक ब्रिटिश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। आर्थिक व अन्य तकनीकी परेशानियों के कारण भारत में रेडियो संचार का विकास बहुत ही धीमी गति से और बाधाओं से लड़ते हुए हो रहा था। वर्ष 1936 में इसे पुनर्जीवन सा मिला जब बीबीसी से आए एक अधिकारी, लियोनल फिल्डन ने भारत के पहले प्रसारण नियंत्रक का पद संभाला। इन्होंने भारतीय प्रसारण सेवा को एक नई दिशा दी। फिल्डन के द्वारा भारतीय रेडियो प्रसारण को दिया गया नाम, ऑल इंडिया रेडियो' आज भी प्रचलित है **(सिंह, 2010)**। बाद में विश्व युद्ध ने भी रेडियो प्रसारण के विकास की गति में एक शिथिलता ला दी। इसके बावजूद बीबीसी या अन्य विदेशी रेडियो चैनलों तथा भारतीय प्रसारण सेवा ने इस काल में सूचना पहुंचाने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही वह समय था जब रेडियो प्रसारण की क्षमता और दक्षता दोनों से लोग प्रभावित हुए और इसे भावी राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जाने लगा। वर्ष 1947 में देश आजाद हुआ, देश की भौगोलिक स्थिति भी साफ हुई। 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्री को सत्ता के हस्तांतरण और इसके बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू के ऐतिहासिक भाषण '*नियति से साक्षात्कार (Tryst with Destiny)'* का सीधा प्रसारण भी ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा किया गया। देशवासियों के लिये हिंदी में इस सेवा का नाम *'आकाशवाणी'* रखा गया। स्वतंत्र भारत के प्रारंभिक दशकों में रेडियो अपनी लोकप्रियता के चरम पर पहुंच गया था। जननायकों के संदेश, देशवासियों की आकांक्षाएं और विकास कार्यों का विस्तार भारत के सुदूर क्षेत्रों तक इसी माध्यम के द्वारा पहुंचना संभव हो पाया। टेलिविजन के आगमन और प्रसार ने रेडियो की लोकप्रियता को कुछ कम जरूर कर दिया। लेकिन रेडियो की सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में पहुंच की क्षमता और साथ ही इसकी कम कीमत ने लोगों को आज तक इससे जोड़ रखा है। भारत की सार्वजनिक रेडियो प्रसारण सेवा ने 1990 के दशक तक अकेले ही रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में राज किया। वर्ष 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रसारण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया कि रेडियो तरंगों पर सरकार का एकाधिकार सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में रेडियो तरंगों को सार्वजनिक संपत्ति घोषित करते हुए, सरकार को निर्देश दिया कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि रेडियो तरंगों का व्यापक उपयोग जनहित में किया जाए ताकि देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सही उपयोग हो सके। वर्ष 1999 में सरकार ने नई एफ.एम. नीति लाकर निजी कंपनियों को रेडियो प्रसारण के लाइसेंस आबंटित किये। इस प्रकार देश में निजी कंपनियों ने भी रेडियो प्रसारण शुरू किया। बाद के वर्षों में विशेष स्थानों और विशेष समुदायों के लिये अलग रेडियो चैनल की मांग की जाने लगी। इसके परिणामस्वरूप देश में सामुदायिक रेडियो पॉलिसी का निर्माण किया गया और इस नीति के तहत शैक्षणिक रेडियो के रूप में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने भी '*ज्ञानवाणी'* नाम से अपने रेडियो प्रसारण सेवा की शुरूआत की । देश के विकास के मुद्दों, खासकर कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर मिशन के रूप में रेडियो प्रसारण समय-समय पर होते रहे। वर्ष 1937 में स्कूल ब्रॉडकास्ट प्रोजेक्ट, एडल्ट एजुकेशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 1956 **(रेडियो फोरम) ,** फार्म एंड होम ब्रॉडकास्ट प्रोजेक्ट 1966, और यूनिवर्सिटी ब्रॉडकास्ट प्रोजेक्ट 1965 जैसी रेडियो प्रसारण परियोजनाओं ने देश में शैक्षणिक रेडियो के विकास में काफी योगदान दिया **(व्यास 2002)**। आज आकाशवाणी के साथ साथ दूरदर्शन के द्वारा भी पूरे देश में अलग अलग भाषाओं और विषयों में शैक्षणिक सामग्री प्रसारित की जा रही है। वर्तमान में देश में रेडियो प्रसारण की तीन प्रकार की सेवाएं कार्यरत हैं, पहली है सार्वजनिक क्षेत्र की आकाशवाणी या ऑल इंडिया रेडियो, दूसरी सेवा निजी कंपनियों द्वारा संचालित कमर्सियल रेडियो सेवा है और तीसरी सेवा है सामुदायिक रेडियो जो किसी समुदाय विशेष के विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखकर कार्यरत है। इंटरनेट और वेब मीडिया के दौर में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के तरीकों में भी कुछ नये अध्याय जुड़े हैं। इंटरनेट रेडियो ,वेब रेडियो, पॉडकास्टिंग या ऑनलाइन रेडियो की अवधारणा समय के साथ प्रसारण क्षेत्रों में हो रहे बदलावों के दौरान ही सामने

आई। इंटरनेट द्वारा उपलब्ध लोकप्रिय और द्रुतगामी प्रसारण क्षमता के बावजूद सामुदायिक रेडियो, प्रसारण में अपना एक अलग स्थान रखता है, लेकिन भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप सेवाएं देने में यह प्रासंगिक है या नहीं यह एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है।

2. शोध का उद्देश्य :

इंटरनेट युग में जहां आज लगभग हर हाथ में मोबाईल फोन हैं, और इंटरनेट के द्वारा संचार की सुविधा बहुत ही कम कीमत में उपलब्ध है, वहीं सामुदायिक रेडियो प्रसारण की संभावनाओं व लाभ के बारे में विस्तृत चर्चा करना ही इस शोध का उद्देश्य है। यह शोध भारत में सामुदायिक रेडियो प्रसारण नीति और उसके द्वारा विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के प्रयासों की भी विवेचना करता है।

3. सामुदायिक रेडियो: अवधारणा एवं परिभाषा

किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र और किसी विशेष समुदाय के लिये होने वाला रेडियो प्रसारण जो उसी क्षेत्र के लोगों के द्वारा संचालित किया जाता है, सामुदायिक रेडियो कहलाता है। असल में यह रेडियो लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चत करने की दिशा में किया जाने वाला प्रयास है। इसीलिये सामुदायिक रेडियो को लोकतांत्रिक रेडियो या समुदाय का, समुदाय के लिये, समुदाय के द्वारा चलाया जानो वाला रेडियो भी कहा जाता है । इतना ही नहीं समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज बनने की इसकी क्षमता ने इसे विकास संचार के माध्यम के रूप में भी स्थापित किया है। अमार्क के अनुसार, सामुदायिक रेडियो एक विशिष्ट मीडिया क्षेत्र है और राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक प्रसारक और वाणिज्यिक निजी मीडिया का एक महत्वपूर्ण विकल्प है। यह समुदायों के लिए अपने मुद्दों और चिंताओं को अपनी भाषा में और सांस्कृतिक रूप से उनके लिए उपयुक्त तरीकों से व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। वहीं यूनेस्को ने अपने विकास लक्ष्यों के लिये भी सामुदायिक रेडियो प्रसारण को महत्वपूर्ण माना है। यूनेस्को के सामुदायिक रेडियो कार्यक्रमों का उद्देश्य सामुदायिक स्तर पर महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों जैसे गरीबी और सामाजिक बहिष्कार को संबोधित करना, हाशिए पर पड़े ग्रामीण समूहों को सशक्त बनाना और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और विकास प्रयासों को गति देना है। सामुदायिक रेडियो की अवधारणा का जन्म द्वितिय विश्वयुद्ध के आस - पास, लैटिन अमरीका से हुआ माना जाता है। इसका प्रारंभ मुख्यधारा की मीडिया के विकल्प के तौर पर हुआ। वास्तव में यह विकास की अवधारणा के साथ जुड़ा हुआ है। यह रेडियो समाज के ऐसे लोगों की आवाज बनता है जो विकास के क्रम में हाशिये पर रह गए, या वंचित और शोषित हों **(फ्रेज़र और एस्ट्राडा, 2001)**। हालांकि बाद के वर्षों में सामुदायिक रेडियो ने विकास के लक्ष्यों का प्रसार ही नहीं किया बल्कि इसके आयाम को भी बढ़ाया। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद नये नये राष्ट्रों का उदय हुआ। इन नये राष्ट्रों ने विकास की अपनी आकांक्षा को मूर्त रूप देने के लिये संचार के साधनों को उपयुक्त जाना और इनमें भी रेडियो तरंगों द्वार होने वाला संचार सबसे ज्यादा महत्वपूण साबित हुआ। प्रत्येक सामुदायिक रेडियो स्टेशन एक परिभाषित मिशन के साथ परिभाषित और लक्षित दर्शकों पर ध्यान केंद्रित करता है। दशकों से सामुदायिक रेडियो स्टेशन भी लोगों के लिए ताकत का स्रोत बनने के लिए विकसित हुए हैं।

सामुदायिक रेडियो एशिया के कई हिस्सों में एक बहुत ही परिचित प्रसारण प्रयोग है। उदाहरण के लिए श्रीलंका में कोठमाले रेडियो स्टेशन। इसका स्वामित्व श्रीलंकाई ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के पास है, यह काफी समय से एक मॉडल के रूप में कार्य कर रहा है। यह स्थानीय ग्रामीण समाज के समर्थन से समुदाय आधारित और भागीदारी में बहुत अच्छा अनुभव दिखाता है **(रासमिन और वानिगासुरेन्द्रा, 2020)**। रेडियो सागरमाथा, नेपाल का पहला स्वतंत्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के साथ साथ एशिया में "स्वतंत्र रेडियो" का पहला प्रयास है। जब यह शुरू हुआ, तो रेडियो स्टेशन का दायरा हिमालयी क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण पर ध्यान केंद्रित करना था। लेकिन जल्द ही रेडियो सागरमाथा नेपाली जनता की आवाज बन गया। नेपाल में अब विभिन्न हिस्सों में कई रेडियो स्टेशनों के साथ एक मजबूत सामुदायिक रेडियो

नेटवर्क है **(दहल, 2020)।** कंबोडिया में, वुमन मीडिया सेंटर, पूरी तरह से महिलाओं द्वारा प्रबंधित और संचालित एक रेडियो स्टेशन है और महिलाओं के विकास के दृष्टिकोण से एक प्रभावशाली भूमिका निभाता है।

4. भारत में सामुदायिक रेडियो के प्रारंभिक प्रयास और पॉलिसी

भारत में सामुदायिक रेडियो प्रसारण के एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में दो दशक पहले ही सामने आया है। लेकिन सरकार के स्वामित्व वाले रेडियो स्टेशनों से जुड़े सामुदायिक प्रसारण कई दशक पूर्व से किये जा रहे हैं। हमारे देश में सामुदायिक रेडियो की व्यापक नीति का निर्माण इसी लंबे संघर्ष का परिणाम है।लंबे संघर्ष के बाद सामुदायिक रेडियो नीति को आकार मिला। एक तरफ रेडियो प्रसारण के लिए नीति निर्माता सामुदायिक रेडियो की अवधारणा के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसी समय कुछ समाजिक संगठनों ने सामाजिक जागरूकता और सामुदायिक विकास के उद्देश्य से सामुदायिक भागीदारी वाली मीडिया परियोजनाओं के साथ इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। इन प्रयोगों और उनके प्रभाव ने सामाजिक विकास मॉड्यूल के रूप में सामुदायिक रेडियो की विश्वसनीयता स्थापित करने में बहुत योगदान दिया था **(पवराला और मलिक, 2007)**। उज्जास रेडियो कच्छ महिला विकास संगठन (केएमवीएस) की सामुदायिक रेडियो परियोजना रही है। 90 के दशक में उज्जास परियोजना, जो ग्रामीण महिलाओं का समाचार पत्र था, में शामिल महिलाओं ने सोचा कि वे अपनी सूचना संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए रेडियो का उपयोग कर सकती हैं। कच्छ एक दूरस्थ और विशाल क्षेत्र है, इस संघ की महिला सदस्य क्षेत्र के विभिन्न दूर-दराज इलाकों से आना जाना करती थीं। उन्होंने महसूस किया कि समुदाय के सदस्यों के साथ संपर्क में रखने और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए रेडियो एक आदर्श तरीका हो सकता है। इसके लिये AIR भुज से एक वाणिज्यिक स्लॉट खरीदा और 30 मिनट का एक साप्ताहिक कार्यक्रम कच्छी भाषा में तैयार किया। कार्यक्रमों में कुछ लैंगिक असमानता और सामाजिक आर्थिक मुद्दों को जोड़ा भी जोड़ा गया। स्थानीय भाषा में प्रसारित होने वाला यह कार्यक्रम इस क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हुआ। इसी प्रकार वर्ष 2000 में आकाशवाणी का डाल्टनगंज स्थानीय रेडियो स्टेशन, झारखंड के एक सुदूर हिस्से में रांची स्टेशन से हिंदी में कार्यक्रम प्रसारित कर रहा था। एआईडी अर्थात अल्टरनेट टू इंडिया डेवलपमेंट संस्था ने पलामू और गढ़वा क्षेत्र में आदिवासी आबादी के बीच काम करते हुए रेडियो के माध्यम से विकास लक्ष्यों तक पहुंचने की योजना बनाई। इनका उद्देश्य विशेष रूप से अधिक वंचितों के बीच सहभागी विकास को बढ़ावा देना था। रेडियो प्रसारण से परिचित होने के बाद इन्होंने स्थानीय स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया। रांची स्थित तकनीकी मीडिया समूह मंथन ने कार्यक्रमों का निर्माण करने में मदद की। प्रारंभिक चरण में स्थानीय स्वयंसेवकों ने सीखा कि कैसे मैदान पर रिकॉर्ड करना, चर्चा करना, अधिकारियों के साथ बातचीत करना और स्थानीय समाचार एकत्र करना है। इनका प्रमुख कार्यक्रम ***चला हो गांव*** में जल्द ही लैंगिक समानता और न्याय से जुड़ी स्थानीय बोली में एकमात्र रेडियो कार्यक्रम के रूप में स्थापित हो गया। कर्नाटक की नम्मा ध्वनी, वॉयस और मायराडा (मैसूर पुनर्वास और पुनर्विकास एजेंसी) की एक सामुदायिक रेडियो परियोजना थी। सितंबर 2001 में, वॉयस ने स्थानीय साथी मायराडा के साथ नम्मा ध्वनि (कन्नड़ भाषा में इसका अर्थ है हमारी आवाज) कार्यक्रम शुरू किया, जो कर्नाटक के बुधिकोट गांव में एक सामुदायिक कार्यक्रम था। बुधिकोट गांव में यूनेस्को के समर्थन से एक स्थानीय ऑडियो प्रोडक्शन सेंटर स्थापित किया गया था। समय के साथ अपने कार्यों के बल पर नम्मा ध्वनि स्थानीय लोगों की आवाज बन गई। डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी (डीडीएस) विभिन्न मुद्दों पर दो दशकों से अधिक समय से ग्रामीण, गरीब और मुख्य रूप से दलित महिलाओं के साथ आंध्रप्रदेश के मेडक जिले के गांवों में काम कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, खाद्य, बीज , प्राकृतिक संसाधन पर स्वायत्तता और बाजार तक पहुंच जैसे मुद्दों पर यह संस्था यहां के लोगों के बीच कार्य कर रही है। वर्ष 1998 में यूनेस्को के समर्थन से डीडीएस ने एक स्थानीय समुदाय के स्वामित्व वाला रेडियो स्टेशन स्थापित करने का प्रयास किया था, लेकिन प्रसारण की अनुमति नहीं मिल पाई। इसके बाद डीडीएस ने ऑडियो प्रोडक्शन शुरू करने का फैसला किया कार्यक्रमों को गांव की महिलाओं तक पहुंचाने के लिए उत्पादन, और नैरोकास्टिंग तकनीकों का उपयोग किया गया। महिला

सशक्तिकरण, क्षेत्रीय विकास, स्वदेशी ज्ञान और संस्कृतियों से संबंधित मुद्दे कार्यक्रम का प्रमुख हिस्सा हुआ करते थे। इन कार्यक्रमों को महिलाओं के संगमों या स्थानीय समूहों के नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित किया जाता था और एक विशिष्ट समय पर रेडियो प्रसारण की तरह सुना जाता था। डीडीएस सामुदायिक रेडियो परियोजना से ही जुड़ी पास्तापुर की दलित महिलाओं के सशक्तिकरण को दुनिया भर में सराहा गया और इससे सामुदायिक रेडियो स्वामित्व की मांग को मजबूत करने में मदद मिली। सामुदायिक रेडियो आज भारत में एक वास्तविकता है। ये सारे प्रयास समुदायों और गैर-सरकारी संगठनों को रेडियो प्रसारण अधिकारों का स्वामित्व प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए नीति परिवर्तन के संघर्ष में सबसे आगे थी। पूरे दक्षिण एशियाई देशों में से सबसे व्यापक प्रसारण नीति भारत द्वारा बनाई गई सामुदायिक रेडियो नीति ही है, जिसमें विकास लक्ष्य और लक्षित समूह के बीच प्रसारण द्वारा संचार को सुगम बनाने हेतु महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये हैं। भारत में सामुदायिक रेडियो नीति ने सामुदायिक भागीदारी और स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायतों, नगर निकायों और राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित संगठनों को पात्रता मानदंड से दूर रखा है। नीति स्पष्ट रूप से सामुदायिक रेडियो, कमर्सियल रेडियो और सार्वजनिक प्रसारण सेवा के बीच अंतर करती है। यह सामुदायिक स्वामित्व की आवश्यकता को पहचानता है और सामुदायिक रेडियो लाइसेंस केवल एक मामूली प्रसंस्करण शुल्क और वार्षिक स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के साथ मुफ्त दिया जाता है जिसे लाइसेंस धारक द्वारा सरकार को भुगतान किया जाता है। इसको साथ ही प्रत्येक रेडियो लाइसेंस स्टेशन के संचालन में सामुदायिक भागीदारी पैदा करने के लिए दिशानिर्देशों के साथ दिया जाता है। भारत में सामुदायिक रेडियो केवल तीन प्रकार के संस्थानों को ही आवंटित किये जाते हैं, ये इस प्रकार हैं-

1- शैक्षणिक संस्थान- कई देशों में कैंपस रेडियो की अवधारण का जन्म किसी शैक्षणिक संस्थान के विशेष आवश्यक्ताओं की पूर्ति के लिये हुआ था, लेकिन भारत में शैक्षणिक संस्थानों को रेडियो स्टेशन को सामुदायिक भागीदारी वाले रेडियो के रूप में चलाना होता है, न कि केवल कैंपस रेडियो के रूप में। आज देशभर के कई शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत सामुदायिक रेडियो, अपने आसपास के समुदायों के विकास के लिये महत्तपूर्ण कार्यक्रम चला रहे हैं।

2- कृषि संस्थान या कृषि विज्ञान केंद्र- कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) और कृषि संस्थानों को विशेष रूप से सामुदायिक रेडियो के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है और कृषि मंत्रालय ने पहले वर्ष में हार्डवेयर खरीद और स्टेशन चलाने के लिए अतिरिक्त धनराशि निर्धारित की है। यह निर्णय भारत में बड़ी संख्या में कृषि समुदायों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। स्थानीय बोली में स्थानीय रूप से आवश्यक मुद्दों पर कृषि और मौसम की जानकारी के प्रसार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ही यह नीति बनाई गई है। केवीके से स्थानीय बाजार की जानकारी, कृषि उत्पादों की बिक्री के अवसर, वैश्विक रुझानों को समझने के लिए इंटरनेट और विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक मंच की पेशकश करने वाले गांवों के लिए स्थानीय ज्ञान केंद्र बनने की उम्मीद है।

3- गैर-लाभकारी, गैर-सरकारी संगठन- इस श्रेणी में स्वामित्व के मुद्दे पर सबसे अधिक बहस हुई है जहां समुदाय एक पंजीकृत निकाय बना सकता है जो सीधे रेडियो लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है। हालाँकि एनजीओ सामुदायिक रेडियो के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन समुदाय आधारित समूह या एनजीओ के लिए सामुदायिक रेडियो केंद्र की स्थापना के लिए कुछ सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है।

हालांकि लाइसेंस की मंजूरी एंटीना की ऊंचाई, ट्रांसमीटर की ताकत और संचालन के लिए सीमा पर सख्त नियंत्रण के साथ आती है। एंटीना को साझा करना या एक से अधिक संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से लाइसेंस धारण करना संभव नहीं है। सामुदायिक रेडियो के लिए भी विज्ञापन समय की अनुमति दी गई है, लेकिन सामुदायिक रेडियो के लिए विज्ञापनों की प्रकृति और स्रोत पर प्रतिबंध है। शैक्षणिक संस्थानों और केवीके के लिए एक सिंगल विंडो क्लीयरेंस है जो एनजीओ सेक्टर या सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के आवेदनों की तुलना में बहुत तेजी से आवेदन पर कार्य करने में मदद करता है। वहीं एनजीओ को गृह मंत्रालय से अतिरिक्त मंजूरी आवश्यक है। सभी आवेदकों को आवेदन के साथ उन समुदायों की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट शामिल करनी होती है जिन्हें रेडियो स्टेशन शामिल करना चाहता है और सेवा करना

चाहता है। एक बार रेडियो स्टेशन स्थापित हो जाने के बाद, एक कार्यक्रम नीति और प्रबंधन समिति बनाना आवश्यक है जहां 50% सदस्य समुदाय से ही होने चाहिए। इसकी विवेचना सूचना और प्रसारण मंत्रालय कड़ी निगरानी द्वारा करता है, साथ ही समय समय पर होने वाले रेडियो सम्मेलनों के द्वारा समुदाय के बीच उल्लेखनीय कार्य करने वाले समुदायों को प्रोत्साहित भी किया जाता है।

5. वर्तमान स्थिति और संभावना

भारत विभिन्न संस्कृतियों और रीति-रिवाजों का देश है। यह न केवल विभिन्न मान्यताओं का देश है, बल्कि भौगोलिक और सामाजिक पहलू भी भिन्न भिन्न हैं। पीढ़ियों से यह भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक अंतर अलग-अलग समुदायों के लिए अद्वितीय वातावरण बनाते रहे हैं। प्रत्येक समुदाय का अपने समुदाय और समाज के भीतर संवाद करने का अपना तरीका होता है। एक जन माध्यम के रूप में रेडियो भारत के लोगों के लिए सुलभ और सस्ती है। जैसा कि प्रत्येक सामुदायिक रेडियो स्टेशन कुछ परिभाषित उद्देश्यों के साथ एक परिभाषित लक्षित श्रोताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। आज देश भर में लगभग 504 (दिसम्बर 2024 तक की स्थिति) पूर्ण रूप से क्रियाशील सामुदायिक रेडियो स्टेशन फैले हुए हैं। प्रत्येक स्टेशन स्थानीय मॉडल का प्रतिबिंब है जिसे वर्षों के अनुभव से बनाया गया है। पिछले कुछ वर्षों में सामुदायिक रेडियो स्टेशन भी लोगों के लिए शक्ति का स्रोत बने हैं। यह उन्हें भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और उन्हे ये भी समझाते हैं कि सामुदायिक रेडियो उन्हें बेहतर जीवन और सामाजिक विकास में कैसे मदद कर सकता है। कुछ सामुदायिक रेडियो स्टेशनों ने कोविड-19 महामारी के समय अपनी सशक्त उपस्थिति और कार्यों से सामुदायिक प्रसारण की संभावना को प्रदर्शित किया। समय- समय पर रेडियो प्रसारण की संभावनाओं और व्यापक जनसमूह तक इसकी पहुंच की क्षमता ने लोगों को प्रभावित किया। यही वजह है कि आज भी राजनेता अपने विचार व्यापक जनसमूह तक पहुंचाने के लिये रेडियो का सहारा लेते हैं। मन की बात कार्यक्रम इसी बात का उदाहरण है, 3 अक्टूबर 2014 से इस कार्यक्रम के प्रसारण की आधिकारिक शुरूआत हुई। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के माध्यम से किया जाता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहा है प्रधानमंत्री की आवाज और विचारों देश के लोगों तक पहुंचाना। भारत जैसे भौगोलिक और सामाजिक विषमताओं से भरे देश में रेडियो ही ऐसा सशक्त माध्यम रहा है जिसने जनसंचार को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण जारी है जिसमें बच्चों, महिलाओं, युवाओं, किसानों, कामगारों से लेकर वनों में रहने वाले आदिम समूहों तक की बात की जाती है। ऐसे सभी विषय जिन्हें मुख्यधारा की मीडिया में कहीं हाशिये पर छोड़ दिया जाता है उन सभी विषयों पर मन की बात कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री के द्वारा चिंतन किया जाता है। इस कार्यक्रम की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नवम्बर 2024 में इसका 116वां संस्करण प्रसारित हुआ, इतना ही नहीं यह कार्यक्रम आकाशवाणी पर प्रसारित होने के साथ ही राष्ट्रीय और वाणिज्यिक प्रसारण सेवाओं में भी इसका प्रसारण होता है। वेबसाइट के माध्यम से देश की आम जनता भी अपने विचार और कार्यक्रम के संदर्भ में अपनी बात ऑडियो या लिखित संदेश के माध्यम से भेजते हैं। वहीं कुछ चुनिंदा फोन कॉल्स को कार्यक्रम में शामिल भी किया जाता है। इस प्रकार मन की बात कार्यक्रम में रेडियो प्रसारण द्वारा सहभागी संचार का सशक्त रूप प्रस्तुत होता है। कुछ प्रदेशों में भी इसी तर्ज पर वहां के मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं और लोगों को शासन की योजनाओं से अवगत कराने के साथ साथ, जनता की आकांक्षाओं को भी जानने का प्रयास कर रहे हैं। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू किया गया रेडियो संवाद कार्यक्रम 'दिल से' भी प्रदेश की जनता में काफी लोकप्रिय रहा, जिसमें नागरिकों से नियमित चर्चा करके विकास कार्य में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी 'संगवारी' नाम से डिजिटल रेडियो की शुरूआत कर, प्रदेश के लोगों को शासन की योजना- परियोजनाओं से अवगत कराया। इसके अलावा भी कई दूरस्थ क्षेत्रों में विशेष लक्ष्य पर आधारित रेडियो स्टेशनों को प्रारंभ किया गया। सामुदायिक रेडियो की बात करें तो वर्ष 2004 में अन्ना एफएम ने भारत के पहले

समुदाय आधारित कैंपस रेडियों के रूप में कार्य शुरू किया। यह सामुदायिक रेडियो ध्वनि तरंगों को लोकतांत्रिक बनाने में शिक्षकों, विद्यार्थियों और समुदाय के सक्रिय योगदान को सुनिश्चित करता है (**प्रभाकर, 2013**)। पूर्व के कुछ शोध के अनुसार अन्ना एफ 90.4 ने नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नॉलॉजी डेवलपमेंट (एनसीएसटीसी) के अभियान साइंस फॉर वीमन (एसएफडब्ल्यू) प्रोजेक्ट के तहत महिला आधारित कार्यक्रम शक्ति- अरियावादी तैयार कर प्रसारित किया। मुख्य रूप से फोन-इन कार्यक्रम के द्वारा स्वास्थ्य, पोषण, पर्यावरण, खाद्य प्रसंस्करण, दिन- प्रतिदिन का विज्ञान आदि विषयों पर कार्यक्रम किये गये। शोध से स्पष्ट हुआ कि इस कार्यक्रम में भाग लेने वाली समुदाय की महिला अब पहले से ज्यादा आश्वस्त हुई है और अपने जीवन पर भी उनका नियंत्रण भी बढ़ा है। राजस्थान के बनस्थली विद्यापीठ द्वारा संचालित रेडियो बनस्थली 90.4 एफएम पर किये गये एक अध्ययन के अनुसार कौशल विकास प्रक्रिया के माध्यम से गांव के स्वयंसेवकों को सशक्त बनाने और वंचित वर्ग से आने वाले प्रतिभागियों के लिये रोजगार के अवसर पैदा करने में यह रेडियो महती भूमिका निभा रहा है। सामुदायिक रेडियो स्टेशन में प्रतिभागियों की भौतिक भागीदारी से उत्पादन और प्रस्तुति कौशल का विकास होता है और अंतत: यह सशक्तिकरण की ओर ले जाता है (**शर्मा एवं सिंह, 2020**)। पिछले 20 वर्षों में इंटरनेट माध्यम भी बड़ी तेजी से लोकप्रिय हुआ है , इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज यह एक क्रांति के नाम से जानी जाती है। इंटरनेट माध्यम अन्य जनमाध्यमों की तरह ही संचार माध्यम तो है ही, लेकिन आज यह एक वैश्विक माध्यम भी बन गया है **(ओहियागू, 2011)**। हालांकि भारत देश की बात करें तो इन्हीं 20 वर्षों में यहां सामुदायिक रेडियो का विकास भी लगातार हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण है सामुदायिक रेडियो का स्थानीय भाषा में होना, जो भारत जैसे भाषिक विविधता वाले देश के लिये सबसे ज्यादा जरूरी है। सामुदायिक रेडियो पर प्रसारण स्थानीय भाषाओं और बोलियों में होता है, अत: लोग इससे आसानी से जुड़ने में सक्षम होते हैं **(मीना एवं सिंह, 2017)** । राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण आयोग के अनुसार 2024 में जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की कुल आबादी का करीब 24 प्रतिशत हिस्सा ही इंटरनेट का उपभोग करता है, उसमें भी करीब 66 प्रतिशत शहरी आबादी क्षेत्र के लोग हैं। इस प्रकार भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अभी भी इंटरनेट की पहुंच और उपयोग से वंचित है, ऐसे में सामुदायिक रेडियो जनसंचार के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाते हैं।

6. निष्कर्ष

देश में दो दशक पहले ही शुरू हुई सामुदायिक रेडियो प्रसारण सेवा, विकास लक्ष्यों की पूर्ति के लिये एक सशक्त माध्यम के रूप में स्थापित हो रही है। सामुदायिक रेडियो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और के समुदायों की आवश्यकताओं और आकांक्षा को पूरा करने में प्रयासरत हैं। सामुदायिक रेडियो की शुरूआत मुख्यधारा के संचार माध्यमों के विकल्प के रूप में हुई थी, आज के इंटरनेट युग में भी यह समाज के दबे, कुचले, शोषित व उत्पीड़ित वर्ग की आवाज के रूप में उभरा है। इंटरनेट युग में भी सामुदायिक रेडियो की प्रासंगिकता बनाए रखने में निम्नलिखित कारक महत्वपूर्ण हैं-

- समुदाय विशेष के द्वारा संचालन और प्रबंधन।
- स्थानीय भाषा में प्रसारण।
- गरीब और अनपढ़ लोगों तक पहुंच और सहभागिता के अवसर।
- भौगोलिक विषमता वाले इलाकों की संचार जरूरत की भी पूर्ति।
- समुदाय के लिये स्थानीय अवसरों और संभावनाओं की उपलब्धता में केंद्रीय भूमिका निभाने की क्षमता।
- सरकारी और गैस सरकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों को समुदाय तक पहुंचाने की क्षमता।
- प्रभावी तरीके से स्थानीय समुदाय में जागरूकता फैलाने की क्षमता।

7. उपसंहार

इक्कीसवीं सदी इंटरनेट संचार क्रांति के अग्रदूत के रूप में जरूर जानी जाती है, लेकिन भारत देश की भाषिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं भौगोलिक विविधता इसे रेडियो संचार के लिये अनुकूल बनाती है। यही वजह है कि आकाशवाणी आज देश की 98 प्रतिशत जनसंख्या तक, 23 भाषाओं और 179 बोलियों में सेवा प्रदान करती है। वहीं बीते कुछ वर्षों में सामुदायिक रेडियो भी अपनी जड़ें विभिन्न समुदायों के बीच जमा रहा है। संचार में जनभागीदारी सुनिश्चत करते हुए, मुख्यधारा की मीडिया से अलग, यह माध्यम हाशिए पर छोड़ दिये गए वंचित लोगों की अवाज बन रहा है और उन्हें सशक्त कर रहा है।

संदर्भ

1. Howley, K. (2009). *Understanding Community Media.* London, Sage publications
2. Luthra, H.R. (1986). *Indian Broadcasting*, New Delhi, Publication Division of India
3. Ohiagu, O. P. (2011). The Internet: The Medium of the Mass Media. *Kiabara Journal of Humanities* 16 (2), 225-232. https://www.researchgate.net/publication/284733552_The_Internet_The_Medium_of_the_Mass_Media
4. Pareek, R., Sharma, L., & Drolia, R. (2023). Community Radio empowering the rural women of Rajasthan in India. *Journal of Communication and Management*, 2(02), 81–87. https://doi.org/10.58966/jcm2023221
5. Pavarala, V. & Malik, K. (2007). Other Voices, The Struggle for Community Radio In India, New Delhi, Sage publications
6. Prabakar, N. (2013*). A study on the role of campus community radio Anna FM in inculcating everyday science awareness among marginalized women* [Anna University]. http://hdl.handle.net/10603/10553
7. Sharma, A. (2015). *Community Radio for Women Empowerment*, New Delhi, Biotech Books
8. Sharma, L., Singh, H., & Shanker, G. (n.d.). Empowering Rural Communities Through Community Radio Training Programmes: A Case Studyof Banasthali Community FM Radio Station. *ResearchGate*, 10(3). https://www.researchgate.net/publication/376991104_EMPOWERING_RURAL_COMMUNITIES_THROUGH_COMMUNITY_RADIO_TRAINING_PROGRAMMMES_A_CASE_STUDY_OF_BANASTHALI_COMMUNITY_FM_RADIO_STATION
9. Shreedhar, R. & Murada, P. (2019). *Community Radio in India*. New Delhi: Aakar Books
10. सिंह, डी,(2010). *भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,* नई दिल्ली, प्रभात प्रकाश

वेब संदर्भ

- https://www.mib.gov.in/broadcasting/community-radio-stations-0
- http://allindiaradio.gov.in/
- http://www.aidindia.com/radio/jhar_chala_ho.php
- http://www.ddsindia.com/www/default.asp